

संपादकीय

आपदा के लिए प्रशंसाकृत

बच्चों का पालन वाले किसी भी व्यक्ति ने इस तरह के सवाल जरूर सुने होंगे 'क्या आपके घर में बचपन में बिजली थी?' 'क्या आपके घर में बचपन में गायें थीं?' और मेरा पसंदीदा सवाल — 'क्या आपके बचपन में डायनासोर हुआ करते थे?' मेरे एक मित्र, जो एक प्रमुख भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं, ने मुझे बताया कि अब ऐमबीए प्रवेश परीक्षा, कैट के माध्यम से उत्तीर्ण होने वाले कई उम्मीदवार हैं, जिनका अतीत के बारे में ज्ञान, जैसा कि अंतिम साक्षात्कारों में पता चला है, काफी हद तक समान है। जब उनसे पूछा गया कि राणा प्रताप ने मुगलों से कब युद्ध किया, तो उनमें से एक ने सोच—समझकर 1960 का अनुमान लगाया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनके दादा ने उस युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी बहुत संभावना है, लेकिन घर पहुंचने पर उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला, तो एक अन्य उम्मीदवार ने 1995 का नाम लिया। और यहाँ एक ऐसा सवाल है जो डायनासोर से मिलता—जुलता है, या लगभग — जब उनसे पूछा गया कि डार्विन ईसा से पहले आए थे या बाद में, तो एक साक्षात्कारकर्ता को पूरा विश्वास था कि विकासवादी जीवविज्ञानी के अपना काम पूरा करने के बहुत बाद ईसा का जन्म हुआ था। और परीकथा के उत्तर लगातार बढ़ते रहते हैं, कभी—कभी बाज साक्षात्कार कक्ष को चमत्कारी क्रेच में बदल देते हैं। सिवाय इसके कि ये बीस की उम्र के लोग हैं, और भविष्य के कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं जो देश के शीर्ष संस्थानों में ऐमबीए करने के लिए कॉम्पनी एडमिशन टेरेस्ट के माध्यम से 97-98 प्रतिशत पर पहले ही अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। यह थोड़ा आश्चर्य की बात है जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि प्रमुख उन्हें नियोग में नियोग दिया जाता है।

इलाकों में तंग बुनियादी ढांचे के कारण भारत के शहरी क्षेत्र आग लगने जैसी घटनाओं के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं। जैसे कि वर्ष 2018 में मुंबई के ईएसआईसी कामगार अस्पताल में आग लगी और 2019 में सूरत कोविंग सेंटर में आग लगने से 22 छात्रों की मौत हो गई। ये घटनाएं बताती हैं कि अतीत की त्रासदियों से पूरी तरह सबक नहीं लिया गया। अतीत में हुए सबसे दुखद उपहार सिनेमा अग्निकांड और भोपाल गैस त्रासदी ने प्रणालीगत सुधारों की जरूरत और उपेक्षा के गंभीर परिणामों को उजागर किया। औद्योगिक सुरक्षा चूक की कई घटनाएं हुई हैं, जो मजबूत शासन और सख्त सुरक्षा नियमों की तत्काल जरूरत को रेखांकित करती हैं। उपहार सिनेमा अग्निकांड एक ऐसी त्रासदी थी, जिसे रोका जा सकता था। 13 जून, 1997 को जब दिल्ली के उपहार सिनेमा में एक लोकप्रिय फिल्म प्रदर्शित हो रही थी, उसी समय खराब ट्रांसफार्मर के कारण आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। ज्यादातर पीड़ित दम घुटने के कारण मरे, क्योंकि वे बालकनी वाले इलाके में निकास द्वार के बंद या बाधित होने के कारण फंस गए थे। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उचित उपायों और आपातकालीन तैयारियों की कमी के कारण यह त्रासदी और भी गंभीर हो गई। इस अग्निकांड की जांच में घोर लापरवाही और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन पाया गया, जैसे कि बचकर भागने के रास्ते बंद थे और अग्निशमन उपकरण उचित रखरखाव के अभाव में खराब थे। उपहार सिनेमा अग्निकांड भवन संहिता (बिल्डिंग कोड) एवं अग्नि सुरक्षा उपायों के सख्त क्रियान्वयन की व्यापक आवश्यकता की याद दिलाता है। यह नियमों के अनुपालन में स्थानीय अधिकारियों की विफलता को भी उजागर करता है, जो शासन के व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है, जिससे केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर निपटने की जरूरत है। अग्निकांड से अलग प्रणालीगत विफलता का एक और उदाहरण है-भोपाल गैस त्रासदी। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा की कमी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। भोपाल में यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का घटनाओं में हजारों लोगों की जान जाती है। बिजली के शॉर्ट-सर्किट, जलनशील सामग्रियों का सही ढंग से भंडारण नहीं करने और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा आग लगने के आम कारण होते हैं। हमारे देश में आग के खतरों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना—राष्ट्रीय भवन संहिता और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नियमित निरीक्षण और गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान रहने से लापरवाही को रोका जा सकता है। जन-जागरूकता और प्रशिक्षण-नागरिकों को अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मॉक ड्रिल (अभ्यास) करने से तैयारी बेहतर हो सकती है तथा मरने वालों की संख्या कम हो सकती है। बुनियादी ढांचे में सुधार-विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित कर आग लगने के सामान्य कारण कम किया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं को बनाना—प्रभावी आपदा प्रबंधन लिए विशेष रूप से शहरी की क्षमताओं पर अग्निशमन विभागों की क्षमताओं पर अप्रतिक्रिया समय में सुधार आवश्यक है। कॉरपोरेट जवाबदारी को लागू करने और सुरक्षा उत्तराधिकारी के लिए कंपनियों को जलवायी ठहराने से औद्योगिक आपदाएँ रोका जा सकता है। उपहार सिनेमा अग्निकांड और भोपाल गैस त्रासदी आग के खतरों और औद्योगिक चूक के विनाशकारी प्रभाव के दिलाती हैं। इनसे निपटने वाले न केवल विनियामक सुधार नियमों को सख्ती से लागू करना की जरूरत है, बल्कि सुरक्षा और तैयारियों को प्राथमिकता की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव जरूरी है। भविष्य की आपदाएँ रोकने और पूरे देश में विभिन्न सुरक्षा के लिए प्रभावी और सक्रिय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

चिंता बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध । रिकॉर्ड्स व्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में हर साल आग लगने की घटनाओं में हजारों लोगों की जान जाती है। बिजली के शॉर्ट-सर्किट, ज्वलनशील सामग्रियों का सही ढंग से भंडारण नहीं करने और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा आग लगने के आम कारण होते हैं। हमारे देश में आग के खतरों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना—राष्ट्रीय भवन संहिता और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नियमित निरीक्षण और गैर—अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान रहने से लापरवाही को रोका जा सकता है। जन—जागरूकता और प्रशिक्षण—नागरिकों को अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मॉक ड्रिल (अभ्यास) करने से तैयारी बेहतर हो सकती है तथा मरने वालों की संख्या कम हो सकती है। बुनियादी ढांचे में सुधार—विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने से आग लगने के सामान्य कारणों को कम किया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना—प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, अग्निशमन विभागों की क्षमताओं और प्रतिक्रिया समय में सुधार करना आवश्यक है। कॉरपोरेट जवाबदेही—सख्त कॉरपोरेट प्रशासन मानकों को लागू करने और सुरक्षा उल्लंघनों के लिए कंपनियों को जवाबदेह ठहराने से औद्योगिक आपदाओं को रोका जा सकता है। उपहार सिनेमा अग्निकांड और भोपाल गैस त्रासदी आग के खतरों और औद्योगिक सुरक्षा चूक के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाती हैं। इनसे निपटने के लिए न केवल विनियामक सुधार और नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, बल्कि सुरक्षा उपायों और तैयारियों को प्राथमिकता देने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव भी जरूरी है। भविष्य की आपदाओं को रोकने और पूरे देश में जीवन की सुरक्षा के लिए प्रभावी शासन और सक्रिय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

केंद्र और राज्यों के समिलित प्रयासों की जरूरत

आदित्य बीते 25 मई को गुजरात के एकोट में गेमिंग जोन में आग ने से बच्चों समेत 32 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने आईटी गठित कर जांच शुरू की दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र ल ने मृतकों के परिवार को चार लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 25 मई की रात ही अचल्ती में आग लगने की दो घटनाएँ—अलग घटनाएं हुईं। विवेक गांवर में बच्चों के अस्पताल में आग लगने से सात नवजात शिशुओं की मौत हो गई और पांच अन्य लोगों ने अलावा, कृष्णगढ़ में एक इमारत में करीब 20 बजे सुबह आग लगी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई और अन्य लोग घायल हो गए। अचल्ती के मुख्यमंत्री अरविंद गोवर्डनीवाल ने अपनी संवेदना व्यक्त की और आश्वासन दिया कि नाओं के कारणों की जांच की जारी रही है, ताकि जिम्मेदार लोगों ने जवाबदेह ठहराया जा सके। आबादी और भीड़भाड़ वाले

के लाग शेष वर्ष सीमा टर की हैं पूरी तीत मेमा नदी रत को रक्षा जो रक्षा को मेमा थी, 13 के प्रेय सीमा रण गाँवों अधि का लोग घायल हो गए। ज्यादातर पीड़ित दम घुटने के कारण मरे, क्योंकि वे बालकनी वाले इलाके में निकास द्वारा के बंद या बाधित होने के कारण फंस गए थे। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उचित उपायों और आपातकालीन तैयारियों की कमी के कारण यह त्रासदी और भी गंभीर हो गई। इस अग्निकांड की जांच में घोर लापरवाही और सुरक्षा उपायों का उल्लंघन पाया गया, जैसे कि बचकर भागने के रास्ते बंद थे और अग्निशमन उपकरण उचित रखरखाव के अभाव में खराब थे। उपहार सिनेमा अग्निकांड भवन संहिता (बिल्डिंग कोड) एवं अग्नि सुरक्षा उपायों के सख्त क्रियान्वयन की व्यापक आवश्यकता की याद दिलाता है। यह नियमों के अनुपालन में स्थानीय अधिकारियों की विफलता को भी उजागर करता है, जो शासन के व्यापक मुद्दों को रेखांकित करता है, जिससे केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर निपटने की जरूरत है। अग्निकांड से अलग प्रणालीगत विफलता का एक और उदाहरण है—भोपाल गैस त्रासदी। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक सुरक्षा

की कमी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर व्यवसाय बंद हुई है। भोपाल में यूनियन गर्बाइड कीटनाशक संयंत्र में विथाइल आइसोसाइनेट गैस का व्यवसाय हुआ, जिसके कारण हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और अधिक लाख से ज्यादा लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ा। यह त्रासदी खराब खरखाव, अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल, अपातकालीन स्थितियों में तैयारी की कमी का नतीजा थी। इसके बाद लंबी कानूनी लड़ाइयां चली और पीड़ितों को देर से न्याय प्रियोंने दी। इस त्रासदी ने औद्योगिक संघर्णों के संचालन में सुरक्षा मानकों को लागू करने और नियमक नियंत्रणी के महत्व को उजागर करके दिया। इसने लापरवाही के लिए अपनियों को जिम्मेदार ठहराने और अस्ती आपदाओं को रोकने के लिए नियंत्रक उपाय सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता को भी प्रदर्शित करके दिया। इस तरह की भयावह टनाओं के बावजूद हमारे देश राज्यों में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे देश में हर साल आग लगने की घटनाओं में हजारों लोगों की जान जाती है। बिजली के शॉर्ट-सर्किट, ज्वलनशील सामग्रियों का सही ढंग से भंडारण नहीं करने और सुरक्षा उपायों की उपेक्षा आग लगने के आम कारण होते हैं। हमारे देश में आग के खतरों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करना—राष्ट्रीय भवन संहिता और अग्नि सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। नियमित नियोक्षण और गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान रहने से लापरवाही को रोका जा सकता है। जन-जागरूकता और प्रशिक्षण—नागरिकों को अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर नियमित मैंक ड्रिल (अभ्यास) करने से तैयारी बेहतर हो सकती है तथा मरने वालों की संख्या कम हो सकती है। बुनियादी ढांचे में सुधार—विद्युत अवसंरचना का आधुनिकीकरण और सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने से आग लगने के सामान्य कारणों को कम किया जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना—प्रभावी आपदा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, अग्निशमन विभागों की क्षमताओं और प्रतिक्रिया समय में सुधार करना आवश्यक है। कॉरपोरेट जवाबदेही—सख्त कॉरपोरेट प्रशासन मानकों को लागू करने और सुरक्षा उल्लंघनों के लिए कंपनियों को जवाबदेह ठहराने से औद्योगिक आपदाओं को रोका जा सकता है। उपहार सिनेमा अग्निकांड और भोपाल गैस त्रासदी आग के खतरों और औद्योगिक सुरक्षा चूक के विनाशकारी प्रभाव की याद दिलाती है। इनसे निपटने के लिए न केवल विनियामक सुधार और नियमों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है, बल्कि सुरक्षा उपायों और तैयारियों को प्राथमिकता देने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव भी जरूरी है। भविष्य की आपदाओं को रोकने और पूरे देश में जीवन की सुरक्षा के लिए प्रभावी शासन और सक्रिय उपाय महत्वपूर्ण हैं।

सियासत के बाद वर्तमान पर ध्यान देने का वक्त

विनाद

चार जून का लाक्सभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद चाहे भी सत्ता में आए, कुछ ऐसे मुद्दे जेनहें अब नजरअंदाज नहीं किया सकता। उम्मीद है कि नई कार कुछ कटु सच्चाइयों पर एक ध्यान देगी। भारत तेजी से ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश बारे में बातें करते हैं। देश के कार्यबल में आर्थिक विकास, चार और उत्पादकता को बढ़ाने क्षमता है। लेकिन अर्थव्यवस्था से बढ़ते उन उच्च शिक्षित और अंगों के लिए पर्याप्त संख्या में बहुत रोजगार सृजित नहीं कर पाते हैं, जो सुरक्षित, ऊचे वेतन वाहाइट कॉलर जॉब की उम्मीद है। रोजगार पाने का मतलब असर कम वेतन वाला, अनिश्चित न करना होता है। पिछले हफ्ते खबर पर मेरा ध्यान गया, मसे पता चलता है कि स्थिति ननी गंभीर है। एक राष्ट्रीय व्यावार की खबर के अनुसार, आईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र

धारज सिस हांस द्वारा दाखल आरटाइड आवेदन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश के 23 आईआईटी के करीब 38 प्रतिशत छात्र अब तक बेरोजगार हैं। समाचार में सिंह के हवाले से बताया गया है कि इस वर्ष सभी 23 में 7,000 छात्रों को आईआईटी कैंपस के माध्यम से नियुक्ति नहीं मिली है। घरिस्फ दो साल पहले यह आंकड़ा इसके लगभग आधा (3,400) था। सिंह ने बताया कि जहां अधिक छात्र बेरोजगार के लिए आवेदन कर रहे हैं, वहीं दो साल में बेरोजगार छात्रों की संख्या 2.3 गुना बढ़ गई है। यदि यह कोई अकेला मामला होता, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन भारत में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी पिछले कुछ समय से बड़ी चिंता का विषय रही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन एवं दिल्ली स्थित थिंक टैंक मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित इंडिया एप्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत के बेरोजगार कार्यबल में 83 फीसदी युवा हैं और कुल बेरोजगार आबादी में माध्यमक या उच्च वर्ष युवाओं की हिस्सेदारी वर्ष 35.2 फीसदी थी, जो बढ़कर 65.7 फीसदी हो 2023 के लिए परिशिष्ट मुख्यतः 2000 और 2022 के आवधिक श्रमबल सर्वे नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट बताती है कि शिक्षित युवाओं का स्तर काफ़ी निम्न है। शिक्षा के स्तर के अनुसार बेरोजगारी दर बड़ी है। सभी उससे ज्यादा शिक्षित युवाओं की दर सबसे ऊपरी है और शिक्षित पुरुषों के बीच शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी ज्यादा है। क्या भारत के शिक्षित युवाओं के लिए गुणवत्ता वाली पर्याप्त नौकरी उपलब्ध है? आंकड़े इसी तरफ इश्वरी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बात यह है कि गरीब परिवर्तित युवा विशेष रूप से परिस्थितियों में हैं।

कम मासिक प्रात व्याकृत व्यवहार क्वाइंटाइल (29.4 प्रतिशत) में मानविक या उच्च-माध्यमिक शिक्षण वाले युवाओं के बीच बेरोजगारी दर उच्चतम क्वाइंटाइल (25.8 प्रतिशत) वाले युवाओं की तुलना में अधिक ही। यहां बता दें कि क्वाइंटाइल किसी आंकड़े को पांच बराबर भागों में विभाजित करती है। नतीजतन युवाओं के बीच उच्च बेरोजगारी दर आंशिक रूप से व्हाइट कॉल जॉब की आकांक्षाओं के कारण हो सकती है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। सबसे गरीब युवाओं के जिनके पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों और सामाजिक पूँजी का अभाव है, वे अधिक पीड़ित हैं तथा चिंता की बात है कि हाशिये पढ़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उच्च शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य श्रेणी के युवाओं की तुलना में ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सामाजिक रूप से हाशिये के युवाओं में उच्च बेरोजगारी उच्चान्वयिताओं का संकेत देती है, जिनके सामना उन्हें बेहतर रोजगार के लिए शस्त्रसे

आकाशका का पूरा करन क लिए करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति सामाजिक विषमताओं को कायम रखती है और सामाजिक रूप से उपर उठने में बाधा उत्पन्न करती है। क्या उच्च शिक्षित युवाओं के लिए शिक्षा के स्तर और नौकरियों के बीच विसंगति समय के साथ बढ़ी है? इंडिया एंप्लॉयमेंट रिपोर्ट, 2024 इस बारे में कुछ संकेत देती है। यह बताती है कि उच्च शिक्षित युवाओं (पुरुष एवं महिला) का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी शामिल हैं, अपनी नौकरी से ज्यादा योग्यता रखते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं में से भी 0.4 फीसदी ऐसे व्यवसायों में लगे हुए थे, जो उनकी योग्यता के अनुरुप नहीं थे। हालांकि समग्र रूप से शिक्षा प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है, जिससे नौकरी की मांग रही है, जो (उच्च शिक्षित और कम शिक्षित युवाओं) में रोजगार दर को कम कर रही है और बेरोजगारी दर बढ़ा रही है। इसके चलते उच्च शिक्षित युवा भी कम कौशल वाले ब्ल्यू-कॉलर जॉब अपनाने लगते हैं। एक

कुशल
ललित
भारत आज दुनिया की सबसे
में से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के
में उभरा है। इसके साथ ही
व गुणवत्ता वाले रोजगार के
सरों का सृजन भी हुआ है, जैसा
नवीनतम आवधिक श्रम सर्वेक्षण
र्शया गया है, जहाँ कई संकेतकों
कारात्मक रुझान देखे जा सकते
15 वर्ष और उससे अधिक आयु
लोगों के लिए श्रमिक-जनसंख्या
पात में लगभग 10 प्रतिशत अंकों
वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में
3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23
66 प्रतिशत हो गया है। इसी
ह, श्रम बल भागीदारी दर में भी
पॉच साल की अवधि में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 57.9 प्रतिशत हो गई है। यह रोजगारी दर में 6 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत की गिरावट से समर्थित था। इस रोजगार परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसमें गतिशील क्षेत्र और उद्यमशील उपक्रम उभरे हैं। लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित कई सरकारी पहलों ने नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमशील प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। साथ ही, भविष्य के लिए तैयार, समावेशी और रोजगार योग्य कार्यबल विकसित करने पर जोर दिया गया है, जिसमें प्रासारिक और अद्यतन कौशल हों, जिन्हें विभिन्न विकास कार्यक्रमों और सरकारी नीतियों द्वारा समर्पित किया गया है, जो भारत के भविष्य को आकार देना जारी रखते हैं। सरकार ने देश में एक जनुकूल रोजगार पारिस्थितिक बनाने के लिए कई प्रभावशक्ती वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ किए हैं। डिजिटल इंडिया, इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास योजना और रणनीतिक क्षेत्रों में उत्पादक प्रोत्साहन योजनाओं सहित जनपहल, कौशल विकास, रोजगार बढ़ाने और उद्यम विकास देने के माध्यम से भारत के मध्यवर्ग योगाओं और नवोदित उद्यमों को विकास के लिए उपलब्ध बनाने की उन्नति की जा रही है।

कौशल
प्रारम्भिक
दिया
के काम
। केंद्र
त और
की तंत्र
ो उपाय
स्किल
यानमंत्री
गारत के
-लिंकड
ेखनीय
क्षमता
बढ़ावा
याकांक्षी
यों का
समर्थन कर रही हैं। उदाहरण दिलए, पीएलआई योजना ने 8 लाख से अधिक नए रोजगार सुरियोजित किए हैं। भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए सरकार ने पूँजीगत व्यय के निरंतर स्तर ने जैसा कि लगातार बजटों में परिलक्षित होता है, बड़े पैमाने पर रोजगार भवित्व पैदा किए हैं। पिछले तीन वर्षों सार्वजनिक पूँजीगत व्यय में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण ने ग्रामीण और शहरी भारत को जोड़ने में मद्दत की है, जिससे नए रोजगार और व्यावसायिक अवसर पैदा हुए हैं। एक मजबूत शिक्षा क्षेत्र मानव पूँजी का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। शिक्षा

नी की चुनौती की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी। शिक्षा तक बहु-मोडल पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं, पीएम ई-विद्या आदि जैसी कई डिजिटल शिक्षा पहल की गई हैं। ऐसी पहलों के सकारात्मक प्रभाव भारत के शिक्षा-वार रोजगार संकेतकों में परिलक्षित होते हैं जो कई सकारात्मक रुझान दिखाते हैं। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊपर के लिए 15 और उससे ऊपर के समूह में डब्ल्यूपीआर 2017-18 में लगभग 43.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 50.3 प्रतिशत हो गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की श्रेणियों के अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो छह साल की अवधि में क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत बढ़ा है। सभी श्रेणियों के लिए एलएफपीआर ने भी समान पैटर्न प्रदर्शित किए, जो रोजगार पर मजबूत शिक्षा नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को पुष्ट करते हैं। चूंकि रोजगार परिदृश्य कौशल-आधारित नियुक्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व में विशिष्ट कौशल सेटों में श्रमिकों को प्रशिक्षित करके रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने की बहुत संभावना है।

कुशल कार्यबल तैयार करने की चुनौती

लिलित

भारत आज दुनिया की सबसे
में से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के
में उभरा है। इसके साथ ही
युणिवर्सिटी वाले रोजगार के
सरों का सृजन भी हुआ है, जैसा
नवीनतम आवधिक श्रम सर्वेक्षण
शर्या गया है, जहाँ कई संकेतकों
कारात्मक रुझान देखे जा सकते
15 वर्ष और उससे अधिक आयु
लोगों के लिए श्रमिक-जनसंख्या
पात में लगभग 10 प्रतिशत अंकों
वृद्धि हुई है, जो 2017–18 में
3 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23
66 प्रतिशत हो गया है। इसी
श्रम बल भागीदारी दर में भी
पाँच साल की अवधि में

उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 57.9 प्रतिशत हो गई है। यह बेरोजगारी दर में 6 प्रतिशत से 3.2 प्रतिशत की गिरावट से समर्थित था। इस रोजगार परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में परिवर्तनकारी परिवर्तन हुए हैं, जिसमें गतिशील क्षेत्र और उद्यमशील उपक्रम उभरे हैं। लाभकारी रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित कई सरकारी पहलों ने नवाचार, रचनात्मकता और उद्यमशील प्रतिभा को बढ़ावा देने वाला एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। साथ ही, भविष्य के लिए तैयार, समावेशी और रोजगार योग्य कार्यबल विकसित करने पर जोर दिया गया है। जिसमें प्रासारिक और अद्यतन

की गुणवत्ता में सुधार, कौशल विकास को बढ़ावा देने और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करने के लिए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की गई थी। शिक्षा तक बहु-मोड़ल पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं, पीएम ई-विद्या आदि जैसी कई डिजिटल शिक्षा पहल की गई हैं। ऐसी पहलों के सकारात्मक प्रभाव भारत के शिक्षा—वार रोजगार संकेतकों में परिलक्षित होते हैं जो कई सकारात्मक रुझान दिखाते हैं। पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा और उससे ऊपर के लिए 15 और उससे ऊपर के समूह में डब्ल्यूपीआर 2017–18 में लगभग 43.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022–23 में 50.3 प्रतिशत हो गया है। स्नातक, स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की श्रेणियों के अनुपात में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो छह साल की अवधि में क्रमशः 6.1 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत बढ़ा है। सभी श्रेणियों के लिए एलएफपीआर ने भी समान पैटर्न प्रदर्शित किए, जो रोजगार पर मजबूत शिक्षा नीतियों के सकारात्मक प्रभाव को पुष्ट करते हैं। चूंकि रोजगार परिदृश्य कौशल—आधारित नियुक्ति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व में विशिष्ट कौशल सेटों में श्रमिकों को प्रशिक्षित करके रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने की बहुत संभावना है।

शीघ्र चुनाव कराने का आह्वान हो सकता

四

संजय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव की तारीख को साल के आखिर से आगे बढ़ाकर 4 जुलाई कर दिया है। कंजर्वेटिवों को उम्मीद थी कि वे अब तक लोकप्रियता के अंतर को पाट लेंगे, और कुछ लोग वास्तव में मानते हैं कि श्री सुनक अभी भी अपनी पार्टी के उद्घारक हो सकते हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें एक भयावह विरासत विरासत में मिली है। लिज ट्रस और बोरिस जॉनसन के पिछले प्रशासन के पतन के बाद, श्री सुनक ने सरकार बनाई, बाजारों को खुश रखा और उत्तरी आयरलैंड पर यूरोपीय संघ के साथ एक तरह का समाधान निकाला। शरद ऋतु 2022 की रिति की तुलना में, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। सरकार का गठबंधन के रूप में माना और कुछ स्थिरता लाई। राजकोष के चांसलर के रूप में अपनी पिछली क्षमता में, उन्होंने व्यक्तिगत और श्रमसाध्य देखभाल की, और उनकी कार्यशैली ने उन्हें देश के हर हिस्से में लोकप्रिय बना दिया। प्रधान मंत्री के रूप में, उन्होंने बहुत कम अहंकार दिखाया है और राजनीति को फिर से अधिक ज्ञानान्यृत बना दिया है। वह एक बार अपनी पार्टी से अधिक लोकप्रिय थे और पार्टी की उम्मीद थी कि वह पार्टी की रेटिंग को अपने स्तर तक ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे कंजर्वेटिव पार्टी को अद्यक देते, यह राजनीतिक और प्रबंधन की भाषा का एक विशिष्ट मिश्रण है। केवल मुद्रास्फीति, जो अब 2.3 प्रतिशत है, को लागू किया गया है। श्री सुनक सरकार की आर्थिक प्राप्ति हुए हैं, तथा जनमत सर्वक्षणों में यह पार्टी पीछे है, कंजर्वेटिव पार्टी को 20 प्रतिशत तथा विपक्षी सत्ता में आए, और वे सहा ढंग से दावा कर सकते हैं कि उन्होंने आर्थिक स्थिरता को थोड़ा-बहुत बहाल किया है, लेकिन कई मुद्दों पर, जैसे कि रवांडा में शरण चाहने वालों को निर्वासित करने की योजना, स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्वीकार्य रूप से लंबी प्रतीक्षा सूची को कम करने का प्रयास, और सीवेज-प्रदूषित जल आपूर्ति को साफ करने के लक्ष्य, सरकार अपने घोषित लक्ष्यों से पीछे रह गई है। यह देखना मुश्किल है कि अगले छह हफ्तों में कंजर्वेटिव कैसे कोई बढ़त हासिल कर सकते हैं। श्री सुनक की समस्या यह प्रतीत होती है कि सफल राजनेताओं के पास दृढ़ विश्वास होते हैं, लेकिन उनका वृष्टिकोण प्रबंधकीय थाय धूमपान पर प्रतिबंध लगाने, उच्च विद्यालय शिक्षा के हाइ-स्पाइ रेलवे लाइन का खत्त करने सहित हल की जाने वाली समस्याओं की एक शृंखला को संबोधित करना। यह रीब्रांडिंग आश्वस्त करने में विफल रही है, और सिविल सेवकों की सरकार ने प्रेरित नहीं किया। उन्होंने सोचा कि कड़ी मेहनत करना और अच्छे इरादे दिखाना पर्याप्त है, लेकिन जैसा कि एक पूर्व सहयोगी ने कहा, शीर्ष पर राजनीति एक कला है, और वे कोई कलाकार नहीं हैं। श्री सुनक की एक मुख्य मान्यता यह है कि राजनीति शेयर बाजार की तरह है — मूलभूत बातों पर विश्वास करो, शोरगुल पर नहीं — शायद यह उनके हेज फंड मैनेजर के रूप में उनके अतीत का प्रतिविंब है। जो उनके लिए फायदेमंद लग रहा था, अब वह नकारात्मक लगता है। सत्ता में 14

जेसीआई चेतना द्वारा तीन दिवसीय व्यावसायिक कार्यक्रम हुआ संपन्न



ब्लूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शहर की सामाजिक संस्था जेसीआई चेतना की अध्यक्ष मीरा अग्रहरी ने तीन दिवसीय व्यावसायिक कार्यक्रम को तीन अलग-अलग दिन दिया है इस तीन दिवसीय व्यावसायिक कार्यक्रम में संस्थाएँ मतगणना कार्मिकों को अवगत कराया है कि उनका द्वितीय साथ में आई कार्ड हुते फोटो ले कर आना आवश्यक है।

